बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 194

औषधि मूल्य नियंत्रण

इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के मुताबिक एक विशेषज्ञ समिति औषधि मूल्य नियामक से यह अनुशंसा करने वाली है कि उसे बिना ब्रांड वाली जेनेरिक औषधियों को दायरे में लेते हुए एंटीबायोटिक औषधियों की कीमतों पर लगी सीमा को तार्किक बनाना चाहिए। फिलहाल ब्रांडेड एंटीबायोटिक औषधियां मसलन ऑगमेंटिन आदि पर स्टॉकिस्ट के लिए मार्जिन की सीमा 8 फीसदी और खुदरा कारोबारियों के लिए 16 फीसदी है। जबकि इस औषधि का थोक मूल्य नियामक तय करता है। यदि राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण राजी हो जाता है तो जेनेरिक एंटीबायोटिक के लिए भी समान नियमन जारी किए जाएंगे। अटकलें हैं कि सबसे अधिक प्रभाव अस्पतालों के मार्जिन पर पड़ेगा। परंतु यह अवसर एंटीबायोटिक औषधियों के मूल्य पर लगी सीमा की दिक्कत को सार्वजनिक करने वाला अवसर भी है। उपभोक्ता कल्याण का काम करने के बजाय वह उसे ही नुकसान पहुंचाने का काम करती है।

कीमतों पर किसी भी तरह की सीमा आरोपित करने का असर आपूर्ति पर पड़ता है। एंटीबायोटिक जैसी दवाओं की आपूर्ति प्रभावित होना कई तरह से नुकसानदेह है। पहली बात, मूल्य नियंत्रण के अधीन खरीदी गई औषधि की कमी आम हो सकती है। यदि कीमतों में ज्यादा कटौती हुई तो दवाओं की राशनिंग हो सकती है। संसाधनों का स्थानांतरण अधिक मुनाफे वाली दवाओं के उत्पादन में हो सकता है जिनकी कीमत पर सीमा न लगी हो। कई कंपनियां चुनिंदा दवाओं को बनाना बंद कर सकती हैं। अन्य कंपनियां चिकित्सकों या अस्पतालों से मिलकर वे दवाएं लिखवाना शुरू कर सकती हैं जो तय कीमत की सीमा से परे हों। ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड जेनेरिक औषधियों के साथ ऐसा हो भी रहा है। दूसरी प्रतिक्रिया समस्या को और विकराल बना सकती है। आपूर्ति संबंधी प्रतिक्रिया का असर गुणवत्ता पर पड़ सकता है। औषधि निर्माता कटौती करेंगे और पर्याप्त नियामकीय निगरानी के वे खराब गुणवत्ता वाली औषधियां बना सकते हैं। चिकित्सकों के गलत पर्चे पहले ही समस्या बने हुए थे और मूल्य सीमा ने हालत और खराब कर दी है। इंडियन बिजनेस स्कूल के शोधकर्ताओं ने टाइप 2 डाइबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा मेटफॉर्मिन पर मूल्य सीमा लागू करने के आपूर्ति एवं मांग पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इसका असर स्पष्ट है। इस दवा की कीमत की सीमा तय किए जाने के बाद विभिन्न कंपनियां आपस में मिलीभगत कर मेटफॉर्मिन के बाजार पर कब्जा बरकरार रखने लगीं। अब तक ऐसा करने के लिए इनमें से किसी कंपनी के खिलाफ कदम नहीं उठाया गया है। बिना क्रियान्वयन की क्षमता के नियमन लागू करना सही नहीं है और इससे बचा जाना चाहिए।

कुल मिलाकर शोध और अध्ययन से यही साबित हुआ है कि देश में औषधि मूल्य नियंत्रण का असर नकारात्मक ही रहा है। वॉशिंगटन डीसी में वैश्विक विकास केंद्र की प्रोफेसर एम्मा डीन ने यह दिखाया है कि देश में मूल्य नियंत्रण का नतीजा ऐसी औषधियों की बिक्री में गिरावट के रूप में सामने आया है। यानी दवाएं कुछ मरीजों की पहुंच से दूर हो जाएंगी। प्रोफेसर डीन के मुताबिक यह विसंगति गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती है।

दवाओं तक बेहतर पहुंच वाले अमीर उपभोक्ता दवाएं आसानी से खरीद सकते हैं। इससे गलत पर्चों की आशंका बढ़ती है। कुछ मरीज इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक औषधियों के साथ ऐसे पर्चे खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि बिना जरूरत के दवा लिखी जा सकती है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मामले में हमारी हालत दुनिया में सबसे बुरी है। खराब दवाओं के कारण हमारे यहां जन स्वास्थ्य संकट में है। अब देश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ रहा है तो हमें दवाओं के मूल्य पर मनमाने नियंत्रण से बचना चाहिए।

अजय मोहंती

सफलता के सफर में मील के नए पत्थर

स्वच्छ भारत अभियान की सफलता से यह उम्मीद बंधी है कि देश जल आपूर्ति हासिल करने और प्लास्टिक कचरे से मुक्ति पाने में भी कामयाब होगा। बता रहे हैं **परमेश्वरन अय्यर**

अहमदाबाद में सुप्रसिद्ध साबरमती नदी के तट पर करीब 20,000 ऐसे सरपंच और स्वच्छाग्रही आज एकत्रित हो रहे हैं जो जमीनी स्तर पर स्वच्छता के लिए काम करते हैं। ये तमाम लोग ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हो रहे हैं जब देश महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम उन्हें एक स्वच्छ भारत की सौगात देने जा रहे हैं जो शायद उन्हें समर्पित की जाने वाली सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। जमीनी स्तर पर स्वच्छता के काम से जुड़े लाखों लोग इस आयोजन को अपने गांवों में लाइव देख सकेंगे। देश की स्वच्छता क्रांति के वास्तुशिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर एकत्रित जनसमूह के साथ-साथ देश को संबोधित करेंगे और उन यादों को ताजा करेंगे जब पांच साल पहले उन्होंने लाल किले के प्राचीर से लोगों के व्यवहार में तब्दीली लाने वाले सबसे बड़े अभियान की शुरुआत की थी।

इस अवधि में देश ने खुले में शौच वाले दुनिया के सबसे बड़े देश से स्वच्छता अभियान का प्रेरक बनने तक का सफर तय किया है। भारत का यह सफर कई देशों के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है और वे भी इस व्यापक सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी प्रभाव वाली चुनौती से निपटने की दिशा में पहल कर रहे हैं। जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी तब भारत में स्वच्छता का कवरेज केवल 39 फीसदी था। महज पांच वर्ष में देश के ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं और करीब 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है। देश के सभी राज्यों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व साथ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे निजी तौर पर एक चुनौती के रूप में लिया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इससे देश के नौ करोड़ से अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण में सहायता मिली। इस बीच सरकार, निजी क्षेत्र और विकास संबंधी क्षेत्रों के बीच जबरदस्त साझेदारी देखने को मिली। सबसे अहम बात यह थी कि यह कार्यक्रम सरकारी योजना से अधिक एक जनांदोलन में तब्दील हो गया।

स्वच्छ भारत मिशन इस बात की मिसाल है कि कैसे एक व्यापक कार्यक्रम का तेज गति से क्रियान्वयन किया जाए। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से इसकी अत्यंत आवश्यकता को महसूस किया गया और देश के विभिन्न राज्यों, जिलों और यहां तक कि गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई। राजनीतिक नेतृत्व एकदम निचले स्तर तक शामिल नजर आया। इस कार्यक्रम ने शौचालयों से जुड़े पूर्वग्रह को समाप्त किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण में इसे प्रमुखता से शामिल किया और छह लाख प्रशिक्षित स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से पंचायतों की बैठक, जन सभाओं में और घर-घर जाकर लोगों में व्यवहार के स्तर पर बदलाव को प्रेरित किया गया। दोहरे पिट वाले स्वउपचारित शौचालयों को देश भर में बढ़ावा दिया गया। देश भर के लोगों ने शौचालय के शुष्क अवशिष्ट को खाली कर शौच से जुड़े कलंक को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में लोगों के व्यवहार में बदलाव पर जोर दिए जाने का एक अर्थ यह भी था कि इस कार्यक्रम में निरंतरता आए। गांवों के लोगों ने प्रेरणा लेकर अपने यहां शौचालय बनवाए और समुदायों में इनके इस्तेमाल को लेकर भी चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। ग्राम सभाओं में छह लाख गांवों ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। हाल ही में सर्वेक्षणों से पता चला है कि शौचालय तक पहुंच रखने वाले 95 फीसदी से अधिक लोग इनका नियमित इस्तेमाल करते हैं।

बहरहाल, अब जबकि इस दिशा में मील का पहला पत्थर हासिल हो चुका है, तो यह सफर जारी रहना चाहिए। हम सभी इस तथ्य से वाकिफ हैं कि व्यवहार में आए बदलाव पर टिके रहने और नए मानक तैयार करने में समय लगा है और इसके लिए मूलभूत संदेश पर बार-बार जोर देना जरूरी होता है। यही कारण है कि गत सप्ताह जारी की गई देश की अग्रसोची 10 वर्षीय स्वच्छता नीति में खुले में शौच मुक्ति को निरंतर जारी रखे जाने को प्राथमिकता दी गई है। यह नीति इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे देश आम जनता को व्यवहार में लगातार बदलाव की चर्चा और संवाद के सहारे खुले में शौच मुक्ति के लाभों से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस दौरान कोई पीछे न छूटने पाए।

राज्यों से भी यह कहा गया है कि वे यदि कोई घर या परिवार किसी तरह पीछे छूट गया है तो उसके यहां शौचालय निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जाए। यह नीति इस बात पर भी केंद्रित है कि हर स्तर पर क्षमता विस्तार हो, वित्तीय सहायता के नए माडल सामने आएं और देश के प्रत्येक गांव में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाए। इस दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को भी तवज्जो दी जाए।

स्वच्छ भारत मिशन सहभागिता वाले विकास की नजीर बन चुका है। यहां सरकार पहल करती है और लोग उस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर जो आह्वान किया था उसके तहत देश भर से करोड़ों लोग स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्लास्टिक कचरे के संग्रह के लिए श्रमदान की पेशकश कर रहे हैं। इस प्रयास का लक्ष्य है प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना। जो भी प्लास्टिक एकत्रित होगा उसे सड़क निर्माण आदि में इस्तेमाल करके सुरक्षित ढंग से निपटाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले कुछ वर्ष के दौरान देश में एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को समाप्त करने की दिशा में एक मजबूत पहल होगी। सरकार सन 2024 तक देश के सभी परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए न्यूनतम संभव स्तर पर एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा। इस योजना में स्रोत की उपलब्धता से लेकर जलापूर्ति और उसके दोबारा उपयोग तक सारी बातें शामिल हैं।

जिस प्रकार देश स्वच्छता के मामले में नए मानक गढ़ने में तैयार रहा, वैसे ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और जलापूर्ति को भी जनांदोलन बनाने का लक्ष्य रहेगा। ऐसे आंदोलनों के पीछे 130 करोड़ लोगों की शक्ति है और इसमें दो राय नहीं कि इसे सफलता मिलेगी।

(लेखक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में सचिव हैं)

क्या जीवनकाल बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को पलटा जा सकता है ?

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

जैव विज्ञान के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय प्रगति हुई है लेकिन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया अब तक रहस्य बनी हुई है। बेहतर पोषण, साफ सफाई तथा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार से जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। नई दवाओं की खोज और आनुवंशिक अनुसंधान से असाध्य रोगों का इलाज संभव हुआ है। उम्मीद की जाती है कि बीते दौर की तुलना में आज मनुष्य बेहतर स्वास्थ्य के साथ ज्यादा लंबे समय तक जीता है। लेकिन क्या मानव प्रजाति दीर्घायु हो सकती है ? हर ऐतिहासिक दौर में ऐसे लोग हुए हैं जो 80 से 90 साल या उससे भी अधिक समय तक जिंदा रहे जबकि तब औसत जीवनकाल 40 से भी कम था।

निश्चित तौर पर हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दीर्घायु होंगे। पूरे यूरोपीय संघ (ईयू) में जीवन प्रत्याशा 80 साल को पार कर गई है और जापान, सिंगापुर और स्विटजरलैंड में तो यह 85 साल से अधिक है। भारत में लोग औसतन 69 साल तक जीते हैं। लेकिन क्या जीवन प्रत्याशा को 120 साल या इससे भी अधिक समय तक पहुंचाना मुमकिन है ? कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा संभव है। इस तरह शोधकर्ताओं और नीतिनिर्माताओं के समक्ष दो परस्पर लेकिन अलग-अलग लक्ष्य हैं। इनमें से एक लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां लोग लंबे समय तक जी सकें और निरोग रह सकें। दूसरा लक्ष्य ज्यादा महत्त्वाकांक्षी है। यह है उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझना और जीवनकाल बढ़ाने के लिए इसके प्रभावों को पलटना।

दुनियाभर में अभी करीब 500,000 लोगों की उम्र 100 से अधिक है। यह संख्या भविष्य में हर दशक में दोगुनी होगी। 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण के मुताबिक मनुष्य के जीवित रहने की कोई सीमा नहीं हो सकती है। इटली की जनसांख्यिकीविद् एलिजाबेटा बार्बी और फ्रांसेस्को लगोना तथा इटैलियन नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने वर्ष 2009 से 2015 के बीच इटली के 105 साल या उससे अधिक उम्र के 3,836 लोगों का रिकॉर्ड खंगाला। हम जानते हैं कि सहज रूप से और सांख्यिकीय रूप से भी हर वयस्क का मरने का खतरा बढ़ जाता है। यानी 20 साल के युवक की तुलना में 21 साल के युवक के अगले 12 महीने में मरने की आशंका थोड़ा ज्यादा है और हरेक साल के साथ यह जोखिम बढ़ता जाता है। इस अध्ययन में एक विचित्र बात सामने आई है कि 105 साल की उम्र के बाद अगले 12 महीने की अवधि के दौरान मरने का जोखिम करीब 50 फीसदी रह जाता है। यह सांख्यिकीय या पद्धति संबंधी संयोग हो सकता है या यह किसी जैविक घटना का संकेत हो सकता है जहां कोशिकाओं की मरम्मत की प्रक्रिया उम्र बढ़ने के प्रभाव को संतुलित करती है।

अंतरिक्ष अनुसंधान और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने वाली संस्था एक्सप्राइज फाउंडेशन ने भी मनुष्यों का जीवनकाल बढ़ाने के अनुसंधान में दिलचस्पी दिखाई है। एक्सप्राइज बोर्ड के एक सदस्य सेर्गेई यंग ने लॉन्जेविटी विजन फंड के लिए 10 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। यह जीवनकाल बढ़ाने से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करेगा। यंग का मानना है कि जीवनकाल को बढ़ाकर 200 साल किया जा सकता है और इसके लिए प्रौद्योगिकी को एक अरब से अधिक लोगों तक मुहैया कराया जा सकता है। एक्सप्राइज के संस्थापक पीटर डाइमेंडिस ज्यादा व्यावहारिक हैं लेकिन इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, 'किसी व्यक्ति के जीवन में 20 से 30 साल जोड़ने का कारोबार धरती पर सबसे बड़ा होगा। जीनोम अनुक्रमण, कृत्रिम मेधा और कोशिकीय दवाओं से ऐसी सफलताएं हासिल होंगी जिससे 100 साल की उम्र 60 की बन जाएगी।' एक्सप्राइज ने हाल ही में जीवनकाल बढ़ाने के बारे में एक सम्मेलन कराया और इसके लिए भविष्य की रूपरेखा भी जारी की। इसमें 12 उन क्षेत्रों का जिक्र है जिनमें सुधार या सफलता से मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सकता है। विज्ञान पत्रिका 'द लान्सट' के मुताबिक 70 फीसदी से अधिक मौतें उम्र संबंधी गंभीर बीमारियों से होती है। इनमें कैंसर, अल्जाइमर्स, दिल की बीमारी और जिगर की बीमारी आदि शामिल हैं।

इन 12 क्षेत्रों में उम्र बढ़ने के आंकड़ों का डेटाबेस तैयार करना, बढ़ती उम्र की प्रक्रिया के शोध के लिए दुनियाभर में स्वीकार्य जैविक मार्कर को वैश्विक मानक बनाना, ऐसे अध्ययनों को दोहराना जिनसे संकेत मिलते हैं कि कैलरी प्रतिबंध से जीवन लंबा होता है, बढ़ती उम्र के साथ होने वाली कम से कम तीन बीमारियों की चेतावनी के लिए परीक्षण, यौवन का कोई भी चक्र जो जानवरों पर कारगर हो, बढ़ती उम्र के साथ पैर पसारने वाली कम से कम तीन बीमारियों की व्यापक इलाज से रोकथाम, पोषक तत्त्वों को संसाधित करने की क्षमता का विश्लेषण, बढ़ती उम्र को सभी प्रक्रियाओं को जोड़ने वाला सिद्धांत और आसान व्यायाम प्रणालियां या व्यायाम के सकारात्मक प्रभावों को दोहराने वाली जैव चिकित्सा प्रणालियां शामिल हैं। ये अध्ययन के अति महत्त्वाकांक्षी लेकिन समझ में आने वाले क्षेत्र हैं। इसके तीन काल्पनिक वैज्ञानिक लक्ष्य हैं। पहला यह कि कम से कम एक साल तक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोककर बढ़ती उम्र को पूरी तरह रोकना। पहले स्तनधारियों पर इसका प्रयोग किया जाएगा और फिर इंसानों पर। दूसरा लक्ष्य मानव शरीर का विस्तृत और सटीक मॉडल बनाना है जिस पर प्रयोग किए जा सकें। इससे शोध पर मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार किया जा सकता है जिसके संभावित फायदे हो सकते हैं लेकिन यह इस विषय के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा लक्ष्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना है। इसके तहत एक व्यक्ति के मस्तिष्क को पूरे सिर के साथ या उसके बिना दूसरे व्यक्ति के शरीर या किसी गैर मानव पात्र में एक साल के लिए हस्तांतरित किया जाएगा जबकि चेतना को बरकरार रखा जाएगा। इससे इस बात का प्रदर्शन होगा कि चेतना को कुछ समय के बाद फिर से हासिल किया जा सकता है। इसे हासिल करने का मतलब होगा अमरत्व।

कानाफूसी

मनमोहन सिंह को निमंत्रण

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के इस वक्तव्य से चकित हैं कि पाकिस्तान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नवंबर में करतारपुर गलियारे के लोकार्पण कार्यक्रम में बुलाएगा। पाकिस्तान, भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए अगले महीने यह गलियारा खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है और उन्हें औपचारिक पत्र जल्द भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंह सिख समुदाय के प्रतिनिधि चेहरों में से एक हैं। उनका जन्म अविभाजित पंजाब के एक गांव में हुआ था लेकिन बतौर प्रधानमंत्री 10 वर्ष के कार्यकाल में वह एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार उन्हें पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान से आश्चर्य हुआ है क्योंकि ऐसा आमंत्रण विदेश मंत्रालय के माध्यम से आना चाहिए।

सावधान रहें सांसद

यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पर कायम रहे तो आई आई टी मद्रास में आयोजित सिंगापुर-भारत हैकाथॉन 2019 में सामने आया एक उपकरण संसद के काम आ सकता है। उपकरण यह पता लगाता है कि किसी कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी कितने गंभीर हैं। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्हें वे कैमरे बहुत पसंद आए जो यह पता लगाते हैं कि कार्यक्रम में शामिल लोग ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि ये कैमरे सांसदों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं और इस बारे में वह लोकसभा अध्यक्ष से बात करेंगे।

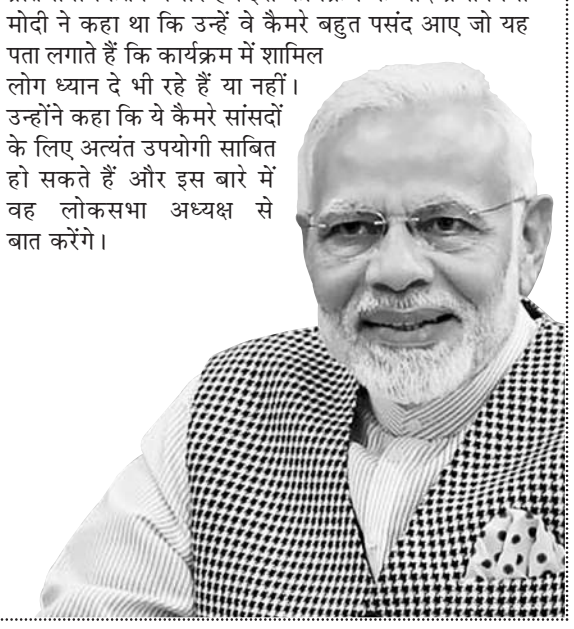

आपका पक्ष

छोड़ना होगा प्लास्टिक पर्यावरण हित में

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। 2 अक्टूबर से ही प्लास्टिक से बनने वाले छह उत्पाद प्लास्टिक थैली, स्ट्रॉ, कप, प्लेट, बोतल और शीट पर रोक लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक भारत को इस तरह के प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से यह बंद नहीं होगा। इसके लिए 135 करोड़ लोगों को स्वयं इसका इस्तेमाल बंद करना होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सहित 18 राज्यों में इसे पहले से ही प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके बावजूद उक्त राज्यों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिगड़ता पर्यावरण दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता है। ऐसे में

प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कोलकाता में जारी जागरूकता अभियान

प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकना और प्लास्टिक कचरे का निस्तारण एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। भारत ने प्लास्टिक के खिलाफ इन्हीं कारणों से जंग छेड़ी है। पहले चरण के तहत एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को बंद किया जा रहा है। दूसरे चरण में प्लास्टिक को इकठ्ठा कर उसे रिसाइकल किया जाएगा। सरकार प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना भी लगाने वाली है। वर्तमान में भारत में 220 लाख टन सालाना प्लास्टिक का उपयोग होता है।

प्रशांत सोलंकी, ईमेल से

आदर्श और प्रेरणा के स्रोत शास्त्री जी

देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही जिससे उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा। धरातल से उठकर भारत के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंच जाने में शास्त्री जी के अपने आंतरिक गुण तथा आदर्शवादी विचारधारा सहायक हुई। शास्त्री भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी काफी गंभीर थे। वे चाहते थे कि दोनों देशों में आगे कोई युद्ध नहीं हो। ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनका निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा देश श्रद्धापूर्वक याद करता है।

अजय प्रताप तिवारी, गोंडा

विश्व के शांतिदूत थे महात्मा गांधी

महात्मा गांधी को विश्व में शांतिदूत के रूप में जाना जाता है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी की विचारधारा को विश्व की महान हस्तियां आज भी सम्मान करते हैं। नेल्सन मंडेला, सर मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर अपने देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ अहिंसा आंदोलन के जरिये अपने अधिकारों को वापस लिया। गांधीजी ने अहिंसा का संदेश दिया लेकिन आज देश में भीड़ की हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे देश की छवि धूमिल हो रही है। गांधीजी राजनेता को जनता का सेवक मानते थे लेकिन कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। गांधीजी के विचारों को सही ढंग से अपनाने में देश अब तक असफल रहा है। देश को अगर सक्षम बनाना है तो गांधीजी के आदर्शों को अपनाना होगा।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।